सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा

"हर सुबह नया जन्म है—कल क्या हुआ, भूल जाओ।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	15°	7°
शनिवार	14 °	7°
रविवार	22°	9°
सोमवार	22°	9°
मंगलवार	16°	8°
बुधवार	16°	8°
वीरवार	16°	7°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 16 JANUARY TO 22 JANUARY 2026 • VOLUME 26 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए सीएम मान, दिया स्पष्टीकरण

कहा- तख़्त साहिब की सर्वोच्च सत्ता में पूर्ण विश्वास, चुनौती देने की ना हिम्मत ना औकात

• **जालंधर ब्रीज.** अमृतसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नंगे पांव अरदास करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष नतमस्तक हुए। श्री अकाल तख़्त साहिब सचिवालय में जत्थेदार साहिब के समक्ष पेश होकर उन्होंने अपने पूर्व बयानों के संबंध में विस्तार से स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने दोहराया कि वे एक विनम्र सिख के रूप में श्री अकाल तख़्त साहिब की सर्वोच्चता में पूर्ण विश्वास रखते हैं और इसके हर निर्णय को सिर-माथे स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पावन संस्था की सर्वोच्चता को चुनौती देने या कमजोर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अकाल तख़्त साहिब सचिवालय में पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे जत्थेदार साहिब के आदेशों का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा, "जत्थेदार साहिब के हुक्म पर मैं यहाँ एक विनम्र सिख के रूप में पेश हुआ और उठाए गए सवालों के उत्तर में अपना स्पष्टीकरण दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब समूचे सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था है और मेरे लिए भी सर्वोच्च है।" मुख्यमंत्री ने बताया कि जत्थेदार साहिब ने उनका बयान दर्ज कर लिया है और सिंह साहिबानों के साथ विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री अकाल तख़्त साहिब के प्रत्येक निर्णय के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं जत्थेदार साहिब के हर फैसले का पालन करूंगा। आज यहाँ पेश होकर मेरे मन को गहरा सुकून, आंतरिक शांति और संतुष्टि मिली है।"

मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख़्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच कथित टकराव को लेकर विरोधी ताकतों द्वारा गढ़े जा रहे कथानक को सिरे से खारिज करते हुए इसे "बेबुनियाद और झूठा" बताया। उन्होंने कहा, "श्री अकाल तख़्त साहिब की अथॉरिटी को चुनौती देने या कमजोर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जो कि समूचे सिख समुदाय के लिए सर्वोच्च है। मेरी सरकार केवल पंजाब की तरक्की और उसके लोगों की भलाई पर केंद्रित है।"

खुद को पंजाब का सेवक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वे पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, "मैं प्रदेश की चढ़दी कला के लिए रोज़ाना अरदास करता हूँ। मेरा सिर हमेशा हर धार्मिक स्थल के आगे झुकता है। यह असंभव है कि मेरा कोई भी कार्य प्रदेश या इसके लोगों के विरुद्ध हो।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि लाखों लोगों की भावनाओं के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जत्थेदार साहिब को 25,000 से 30,000 पन्नों की शिकायतें सौंपी हैं। उन्होंने कहा, "ये शिकायतें उन लोगों की भावनाओं को दर्शाती हैं, जिन्होंने शिरोमणि कमेटी के कामकाज में विभिन्न अनियमितताओं को उजागर किया है। मैंने विनम्रता से निवेदन किया है कि इन शिकायतों की जाँच करवाई जाए, क्योंकि लाखों लोगों की भावनाएँ इससे जुड़ी हैं। संस्थाएँ हमेशा सर्वोच्च होती हैं, पर उनके मुखिया गलती कर सकते हैं; ऐसे व्यक्तियों के गलत कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "श्री अकाल तख़्त साहिब का हर हुक्म मुझे सिर-माथे स्वीकार है, क्योंकि यह सिखों की सर्वोच्च संस्था है। मैं और मेरा परिवार इस सर्वोच्च संस्था के आदेशों का पालन करते हैं।" उन्होंने जत्थेदार साहिब का धन्यवाद किया कि उन्होंने सिख रहित मर्यादा और गुरुद्वारा एक्ट से संबंधित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें भेंट कीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लापता सरूपों की जाँच के लिए विशेष जाँच टीम (एसआईटी) के गठन पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। उन्होंने कहा, "एसआईटी की जाँच का उद्देश्य केवल लापता सरूपों का पता लगाना है, ताकि उनकी किसी भी प्रकार की दुरुपयोग की संभावना न रहे।" उन्होंने बताया कि उन्होंने जत्थेदार साहिब से अनुरोध किया है कि शिरोमणि कमेटी को निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि उनके द्वारा प्रकाशित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रत्येक सरूप को दिया गया विशिष्ट (यूनिक) कोड उपलब्ध कराया जाए, जिससे लापता सरूपों का पता लगाया जा सके।

शिक्षा आजीविका मात्र का साधन नहीं है, यह समाज और राष्ट्र की सेवा का भी एक साधन है : राष्ट्रपति

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं द्रौपदी मुर्मु

• **जालंधर ब्रीज.** अमृतसर

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र अलग-अलग दिशाओं में अपना सफर शुरू करेंगे। कुछ सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवा करेंगे, कुछ उच्च शिक्षा या अनुसंधान करेंगे, जबकि कई अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे या शिक्षण में अपना करियर बनाएंगे। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं और कौशलों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ गुण हर क्षेत्र में प्रगति के लिए समान रूप से आवश्यक और सहायक होते हैं।

ये गुण हैं - सीखने की निरंतर इच्छा और लगन; प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का दृढ़ पालन; परिवर्तन को अपनाने का साहस; असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प; टीम वर्क और सहयोग की भावना; समय और संसाधनों का अनुशासित उपयोग; और ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के व्यापक हित के लिए करना। उन्होंने कहा कि ये गुण न केवल उन्हें एक अच्छा व्यवसायी बनाएंगे, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाएंगे। राष्ट्रपति ने छात्रों को याद दिलाया कि शिक्षा केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का भी साधन है। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने उन्हें शिक्षा प्रदान की है, उसके प्रति वे ऋणी हैं। विकास की राह में पिछड़ चुके लोगों के उत्थान के कोशिश करना इस ऋण को चुकाने का एक तरीका हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज कृषि से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक, युवाओं के लिए अनेक उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध हैं।

जांच एजेंसी के काम में दखल गंभीर मामला, बंगाल सरकार और पुलिस को नोटिस

कोलकाता. ममता बनर्जी को आज उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी की काम में पुलिस की दखल का मामला गंभीर है। कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही, ईडी के छापे से जुड़ी सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ईडी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और पश्चिम बंगाल सरकार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डीसीपी प्रियबत्रा रॉय सहित प्रमुख पुलिस अधिकारियों को एजेंसी की छापेमारी में कथित हस्तक्षेप के लिए निलंबित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने कहा, "यह एक बेहद चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। पहले भी, जब भी वैधानिक प्राधिकरणों ने वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है, मुख्यमंत्री जबरदस्ती उनके परिसर में घुस जाती हैं। एसजी मेहता ने कहा कि डायरेक्टर और कमिश्नर उनके साथ थे। वे सहयोगी थे। अधिकारियों ने राजनीतिक नेताओं के साथ धरना दिया।

40 किलो हेरोइन की खेप सहित चार काबू

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने नारकोटिक तस्करी मॉड्यूल के चार संचालकों को 40 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार करके इसका पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान नरिंदर सिंह उर्फ नन्नी, सूरज, जैकब मसीह और अजय कुमार उर्फ रवि, सभी निवासी कोट ईसे खां, मोगा के रूप में हुई है। हेरोइन बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने नशों की खेप ले जाने के लिए इस्तेमाल की जा रही कारें टोयोटा कोरोला एल्टिस (रजिस्ट्रेशन नंबर पी.बी.03ए.के.1810) और बी.एम.डब्ल्यू. (रजिस्ट्रेशन नंबर यू.पी.14 सी.जे.4646) को भी अपने कब्जे में ले लिया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार मुलजिमों ने हेरोइन की बड़ी खेप अपने हैंडलर, जो नशा तस्कर है, के निर्देशों पर पंजाब में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने के लिए प्राप्त की थी। पुलिस टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते

हुए अमृतसर-तरनतारन हाईवे पर नाका लगाया और डीपीएस स्कूल, अमृतसर के निकट नरिंदर सिंह उर्फ नन्नी, सूरज, जैकब मसीह और अजय कुमार को रोककर उनकी तलाशी ली और उनके कब्जे से 40 किलो हेरोइन बरामद की। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले-पिछले संबंधों और समूची सप्लाई चेन, जिसमें अंतर-सीमा संबंध होने की संभावना है, का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

पंजाब सरकार द्वारा स्कूलों के समय में बदलाव, अब स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य के स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है अब, प्राथमिक स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक संचालित होंगे। यह संशोधित समय 21 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा, "हमारे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने स्कूल प्रमुखों और जिला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओ.) को राज्य भर के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में इस संशोधित समय-सारणी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

जालंधर की अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का फर्जी वीडियो तुरंत हटाने के दिए आदेश

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर/चंडीगढ़

जालंधर की एक अदालत ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी से संबंधित फर्जी वीडियो मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें साबित हुआ कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और यह फर्जी थी, अदालत ने इसे सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, 'x' और टेलीग्राम को 24 घंटों के अंदर इस फर्जी और छेड़छाड़ की गई वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। गलत जानकारी के प्रसार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिए हैं कि साइबर क्राइम विभाग से जानकारी मिलने पर ऐसी किसी भी वीडियो को तुरंत हटाया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसी फर्जी सामग्री के प्रसार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'आप' पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि एक बार फिर भाजपा के झूठ, फरेब और गलत इरादे पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान, भाजपा ने हमारी वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी का नाम विधानसभा में हमारे सम्मानित गुरुओं की कथित बेअदबी से जोड़कर खुलेआम झूठ फैलाने की कोशिश की।

नवाचार, समावेशन और भारत की प्रगति को गति देते हैं स्टार्टअप

जालंधर ब्रीज. नई दिल्ली

स्टार्टअप इंडिया पहल पूरे देश में एक समग्र और नई सोच वाले इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुई है। यह युवाओं की उद्यमशील ऊर्जा को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को तेज करने की दिशा में लगाकर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के मिशन को साकार करने का मार्ग तैयार कर रही है। भारत में आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक मौजूद है। आज उद्यमिता एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी है, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और विकास व रोजगार सृजन का नया इंजन बन रही है। यह परिवर्तन रातोंरात नहीं हुआ। जब प्रधानमंत्री ने 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की, तब उन्होंने एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दृष्टि रखी कि उद्यमिता देश के हर जिले और हर ब्लॉक तक पहुंचे। 16 जनवरी 2016 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से शुरू किए जाने के बाद से स्टार्टअप इंडिया ने लंबा सफर तय किया है। स्टार्टअप देश की अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊर्जा भर रहे हैं। आईटी सेवाएं, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान, शिक्षा, कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसके अलावा, जलवायु तकनीक और अवसंरचना सहित 50 से अधिक अन्य उद्योगों में भी नए उद्यम सामने आए हैं। यह व्यापकता विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और मजबूती को दर्शाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

श्री पीयूष गोयल

नवाचार और एआई: पिछले एक दशक में एक बड़ा बदलाव नवाचार और गहन तकनीक पर बढ़ते ध्यान के रूप में देखा गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर पिछले वर्ष 38वें स्थान पर पहुँच गई है, और गहन तकनीक से जुड़े स्टार्टअप्स को सरकार का समर्थन इसे आगे और बेहतर करेगा। प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के आधार पर एआई स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

गहन तकनीक वाला राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, तथा इंडिया एआई मिशन और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना की शुरुआत की गई है। भारत के स्टार्टअप एयरोनॉटिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा, रोबोटिक्स, हरित तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार कर रहे हैं। बौद्धिक संपदा के निर्माण में तेज़ वृद्धि इस प्रवृत्ति को और मजबूत करती है। भारतीय स्टार्टअप्स ने 16,400 से अधिक नए पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं, जो मौलिक नवाचार, दीर्घकालिक मूल्य सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

60 से अधिक नियामकीय सुधारों के माध्यम से अनुपालन का बोझ कम किया गया है, पूंजी जुटाने को आसान बनाया गया है और घरेलू संस्थागत निवेश को मजबूत किया गया है। एंजेल टैक्स को समाप्त करने और वैकल्पिक निवेश कोषों (एटीएफ) के लिए दीर्घकालिक पूंजी के रास्ते खोलने से स्टार्टअप फंडिंग का पारिस्थितिकी तंत्र और सशक्त हुआ है। बाज़ार तक पहुंच को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जैम) के माध्यम से 35,700 से अधिक स्टार्टअप्स को जोड़ा गया है, जिन्हें 51,200 करोड़ से अधिक मूल्य के पांच लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। इन प्रयासों के साथ मजबूत वित्तीय सहयोग भी दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के तहत वैकल्पिक निवेश कोषों के जरिए 25,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है, जिससे 1,300 से अधिक उद्यमों को लाभ मिला है। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत 800 करोड़ से अधिक के बिना जमानत ऋण की गारंटी दी गई है।

सांस्कृतिक बदलाव: भारतीय स्टार्टअप्स ने देश में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन लाया है। पहले बच्चों को मुख्य रूप से सरकारी नौकरी, इंजीनियरिंग या चिकित्सा जैसे कुछ ही क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज कई युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनने का सपना देख रहे हैं, और उनके परिवार भी उद्यमशील आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। अंततः भारत की स्टार्टअप यात्रा: हमारे युवा उद्यमियों पर विश्वास, नीति-आधारित विकास और दुनिया के लिए नवाचार करने की भारत की क्षमता की कहानी है। 2047 तक एक विकसित देश बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, स्टार्टअप्स समृद्ध, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

ठेका आधारित कर्मचारी को 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा

जालंधर (जालंधर ब्रीज). पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान, डायरेक्टर, लैंड रिकॉर्ड विभाग, पंजाब के कार्यालय में तैनात ठेका आधारित कर्मचारी परवेश को शिकायतकर्ता से उसकी जमीन के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बदले 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आरोपी को गांव छोकरा, तहसील दसूहा, जिला एसबीएस नगर के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि उसकी शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसमें आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के थाना जालंधर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

भारत से 16698 किमी दूर है ये देश, फ्लाइट से जाने में लगते हैं 30 घंटे

Travelling भारत के करीबी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या सबसे दूर देश चिली का नाम सुना है। चिली भारत से हजारों किमी दूर है और सुंदर देश है। चलिए इसके बारे में ...

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

दुनियाभर में ऐसे कई देश हैं, जो अपनी अलग खासियत की वजह से जाने जाते हैं। इन देशों को देखना हर किसी का सपना होता है और लोग वहां पहुंचते भी हैं। लेकिन क्या आपने भारत से सबसे ज्यादा दूरी वाले देश चिली के बारे में सुना है। चिली को दुनिया का सबसे लंबा और पतला देश कहा जाता है, जो भारत से लगभग 16698 किमी की दूरी पर बसा हुआ है।

चिली जाने के लिए नई दिल्ली से अगर आप फ्लाइट लेते हैं, तो वो आपको 30-35 घंटे में पहुंचाएगी। इस बीच कई स्टॉप दिए जाते हैं।

इस रूट के लिए जो सबसे तेज फ्लाइट है, वो भी 27 घंटे से कम की नहीं है। चिली देश काफी सुंदर और संकरा हैं। चलिए इसके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं।

क्या है खासियत

चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी सैंटियागो है और यहां की आम भाषा स्पैनिश है। मैप के अनुसार, चिली लंबा और पतला देश है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 91 किमी है। यही कारण है कि इसे दुनिया का पतला देश कहा जाता है। इसकी तटरेखा की बात करें तो ये 6437 किमी से ज्यादा है। यहां पर चिलियन पेसो करेंसी चलती है। ये देश दक्षिण अमेरिका के सबसे स्थिर और समृद्ध देशों में से एक है। यहां सभी लोग खुशहाल जीवन जीते हैं और मस्त रहते हैं।

ग्लेशियर-रेगिस्तान

चिली देश में ग्लेशियर से लेकर रेगिस्तान तक सबकुछ देखने को मिलेगा। यहां पर नेचुरल ब्यूटी के लिए अटाकामा रेगिस्तान, एंडीज पर्वत, पेटागोनिया आइस फील्ड फेमस है। लोग यहां घूमने जरूर जाते हैं। खूबसूरत जगहों के अलावा चिली अपने खान-पान और वाइन के लिए मशहूर है। चिली ठंडा देश माना जाता है और इस वजह से यहां पर ज्यादातर लोग नॉन-वेज खाते हैं। यहां पर वेज खाना कम खाया जाता है और यहां की वाइन दुनियाभर में मशहूर है।

कैसे जाएं

अगर आप चिली घूमने जाना चाहते हैं, तो भारतीयों को चिलियन वीजा की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीजा है, तो उसके जरिए भी चिली जा सकते हैं। वरना आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा और इस प्रॉसेस में 12-15 दिन लगते हैं। इसके अलावा आपको कई दस्तावेजों को जमा करना होगा।

LIFESTYLE

बोले बगैर लोग लगा लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा, इन चीजों को करते हैं नोटिस

जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके एक भी शब्द बोलने से पहले ही वो आपकी इन 5 चीजों को सबसे पहले नोटिस करता है और आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। एटिकेट कोच ने बताया हमेशा इन 5 चीजों पर फोकस करें।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

जुबां के लहजे से इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहली बार में इंसान को देखकर लोग उसके व्यक्तित्व के बारे में एक राय बना लेते हैं।

तभी कहा जाता है ना 'फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट'। अपनी नॉलेज और स्पीकिंग के साथ ही ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। अक्सर जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो सबसे पहले उसकी नजर इन चीजों पर होती है। एटिकेट एंड एलिगेंस कोच मानिक कौर ने ऐसे ही 5 चीजों को बताया है। जिन्हें लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को जज करने करते हैं।

आपके पैर

जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसकी निगाह आपके पैरों पर होती है। गंदे जूते, खुरदुरे पैर, पुरानी नेलपॉलिश लगे गंदे पैर आपके इंप्रेस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपनी ग्रूमिंग में पैरों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है।

फेशियल एक्सप्रेशन

जब आप किसी से मिलते हैं तो चेहरे के भाव पर हर किसी की निगाह होती है। भले ही हर समय आप स्माइल ना करें लेकिन चेहरे पर इरिटेट होने या फिर बातों में इंटरेस्ट ना दिखाने वाले भावों को भी ना लाएं। इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। चेहरे पर हल्की सी ग्रेसफुल स्माइल बनाकर रखें। इससे आप पॉजिटिव नजर आएंगे।

आपका परफ्यूम

मानिक कौर बताती हैं कि अक्सर लोग आपके कपड़ों को भूल सकते हैं। लेकिन खास तरह की स्मेल को नहीं भूल पाते हैं। इसलिए गुड परफ्यूम और स्मेल को ग्रूमिंग में जरूर शामिल करें।

आपका पोश्चर

आप किसी से एक शब्द नहीं बोलेंगे तो भी आपके पोश्चर को देखकर लोग पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाएंगे। इसलिए हमेश कॉन्फिडेंट होकर चलिए।

आपके कपड़े

जरूरी नहीं कि डिजाइनर और महंगे कपड़े पहनने पर ही लोग नोटिस करते हैं। साफ-सुथरे, अच्छी तरह से आयरन किए हुए कपड़ों को पहनकर रेडी हों। ये आपकी वेल ग्रूमिंग को दिखाता है। तो अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें तो इन 5 बातों का ख्याल जरूर रखें। क्योंकि ये वो बातें हैं जिनसे लोग आपको अक्सर जज करते हैं।

झटपट तैयार होगा ये चटपटा पनीर टिक्का, वो भी बिना ओवन और तंदूर

अगर आपके पास तंदूर या ओवन नहीं है, फिर भी टेस्टी पनीर टिक्का बनाना चाहते हैं, तो यह आसान स्टोवटॉप रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। कम तेल, ज्यादा स्वाद और जबरदस्त फ्लेवर के साथ।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

रेस्टोरेंट जैसा स्मोकी और मसालेदार पनीर टिक्का खाने का मन हो, लेकिन घर में तंदूर या ओवन ना हो तो क्या स्वाद से समझौता करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सही मैरिनेशन, संतुलित मसाले और स्टोवटॉप कुकिंग तकनीक से आप घर पर भी उतना ही लाजवाब पनीर टिक्का बना सकते हैं।

आजकल लोग हल्का, प्रोटीन-रिच और कम तेल वाला खाना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में पनीर टिक्का एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि पेट के लिए भी हल्का रहता है। सही तरीके से बनाया जाए तो इसमें बाहर से हल्की क्रिस्पी लेयर और अंदर से सॉफ्ट व जूसी टेक्सचर मिलता है- ठीक वैसा जैसा ढाबों और रेस्टोरेंट्स में।

इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें ओवन, एयर फ्रायर या तंदूर की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक कढ़ाही या नॉन-स्टिक पैन से आप शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। दही-आधारित मैरिनेशन मसालों को पनीर के अंदर तक पहुंचाता है, जबकि हल्की धीमी आंच पर सेकने से फ्लेवर लॉक हो जाता है। चाहे शाम की भूख हो, मेहमानों के लिए स्टार्टर बनाना हो या हेल्दी स्नैक की तलाश- यह घरेलू पनीर टिक्का रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है।

बिना तंदूर और ओवन के, सिर्फ गैस पर कैसे तैयार करें रेस्टोरेंट-स्टाइल, स्मोकी और टेस्टी पनीर टिक्का-

सामग्री

250 ग्राम पनीर (क्यूब्स में कटा हुआ),1 शिमला मिर्च (चौकोर टुकड़ों में), 1 प्याज (चौकोर टुकड़ों में), ½ कप गाढ़ा दही, 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला, ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी (मसलकर), 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 1-2 बड़े चम्मच तेल।

बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़े बाउल में दही लें और उसमें सभी मसाले, अदरक-लहसुन पेस्ट, कसूरी मेथी, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।

अब इसमें पनीर, प्याज और शिमला मिर्च डालें और हल्के हाथ से मिलाएं ताकि पनीर टूटे नहीं।

इस मिश्रण को कम से कम 30-40 मिनट के लिए मैरीनेट होने दें। जितना ज्यादा समय देंगे, उतना स्वाद बढ़ेगा।

अब गैस पर नॉन-स्टिक पैन, तवा या कढ़ाही गरम करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें। मैरीनेट किया हुआ पनीर और सब्जियां पैन में रखें और मध्यम आंच पर चारों तरफ से पलट-पलट कर सेकें।

जब पनीर के किनारे हल्के ब्राउन और सब्जियां नरम हो जाएं, तब गैस बंद कर दें।

अगर आप स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं, तो जलते हुए कोयले को एक कटोरी में रखकर उस पर थोड़ा तेल डालें और पैन को ढक दें। 1-2 मिनट में टिक्का में तंदूरी खुशबू आ जाएगी।

गरमा-गरम पनीर टिक्का को हरी चटनी और नींबू के साथ परोसें। यह पार्टी स्नैक, शाम की चाय या हेल्दी स्टार्टर के लिए एकदम परफेक्ट है।

PARENTING

टॉपर बनना कोई पैदाइशी हुनर नहीं, ये 5 माइंडसेट औसत छात्रों को भी बना देते हैं कामयाब

जालंधर ब्रीज (फीचर) . सफलता का असली रहस्य किताबों के ढेर या परीक्षा के अंकों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के उस 'कंट्रोल रूम' में छिपा है जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टॉपर बच्चों में अनुवांशिक गुण छिपे होते हैं। लेकिन आधुनिक शोध इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। दरअसल , एक औसत छात्र और एक टॉपर बच्चे के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी मेहनत नहीं, बल्कि चुनौतियों को देखने का उनका नजरिया होता है। जब आप अपनी क्षमताओं को 'स्थिर' मानने की जगह उन्हें 'विकसित' करने वाला मान लेते हैं, तो दिमाग के सीखने की गति अपने आप बढ़ जाती है।

'स्मार्ट हूं या नहीं' से 'मैं ग्रो कर सकता हूं' की ओर शिफ्ट : कई छात्र सोचते हैं कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है,जबकि सफलता की राह में यह सोच गलत और हानिकारक है। ग्रोथ माइंडसेट में विश्वास करें कि मेहनत से क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं। इसके लिए 'मैं इसमें अच्छा नहीं हूं' की जगह 'मैंने इसे अभी तक मास्टर नहीं किया है' सोचें। गलतियों को सीखने का मौका मानकर आगे बढ़ते चलें।

पैसिव रीडिंग से एक्टिव रिट्रीवल की ओर शिफ्ट : नोट्स बार-बार पढ़ना कम प्रभावी है, याद करके निकालना (एक्टिव रिकॉल) बेहतर है। इसके लिए आप खुद को क्विज करें, फ्लैशकार्ड्स इस्तेमाल करें या किसी को समझाकर बताएं। सेल्फ-रेगुलेशन में प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिफ्लेक्शन को शामिल करते हुए स्टडी टाइम को सेगमेंट्स में बांटें, स्पेसिफिक गोल्स सेट करें और प्रोग्रेस ट्रैक करें।

फीलिंग्स अवॉइड करने की जगह एग्जाम एंग्जायटी मैनेज करने पर दें ध्यान : कई बच्चों को परीक्षा से पहले एंग्जायटी फील हो सकती है। ऐसे में उसे दबाना उल्टा पड़ सकता है। इसे जर्नलिंग से हैंडल करें। इसके लिए टेस्ट से पहले चिंताओं को लिखें। 'मैं नर्वस हूं लेकिन मैं तैयार हूं', ऐसा माइंडसेट बनाकर रखें।

बड़े ऑब्जेक्टिव्स से छोटी सफलताओं की ओर शिफ्ट : बड़े गोल्स ओवरव्हेल्मिग होते हैं जबकि छोटे सब-गोल्स मोटिवेशन बढ़ाते हैं। पूरी 'केमिस्ट्री पढ़नी है' की जगह 'pH फॉर्मूला मास्टर करना है' या 'एक सैंपल पेपर पूरा करना है' जैसे गोल्स सेट करें।

रटने की मानसिकता को बदलकर सेल्फ-रेगुलेशन की ओर शिफ्ट करें : रटना व्यस्तता का भ्रम देती है जबकि सेल्फ-रेगुलेशन में प्लानिंग, मॉनिटरिंग और रिफ्लेक्शन शामिल है।

डिस्क्लेमर : इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रील पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

नाश्ते में फल खाकर भी रहें फिट, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सही तरीका

Health सुबह फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, अगर सही तरीके से किया जाए। न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हैं कि नाश्ते में फल कब, कैसे और किन चीजों के साथ खाने चाहिए।

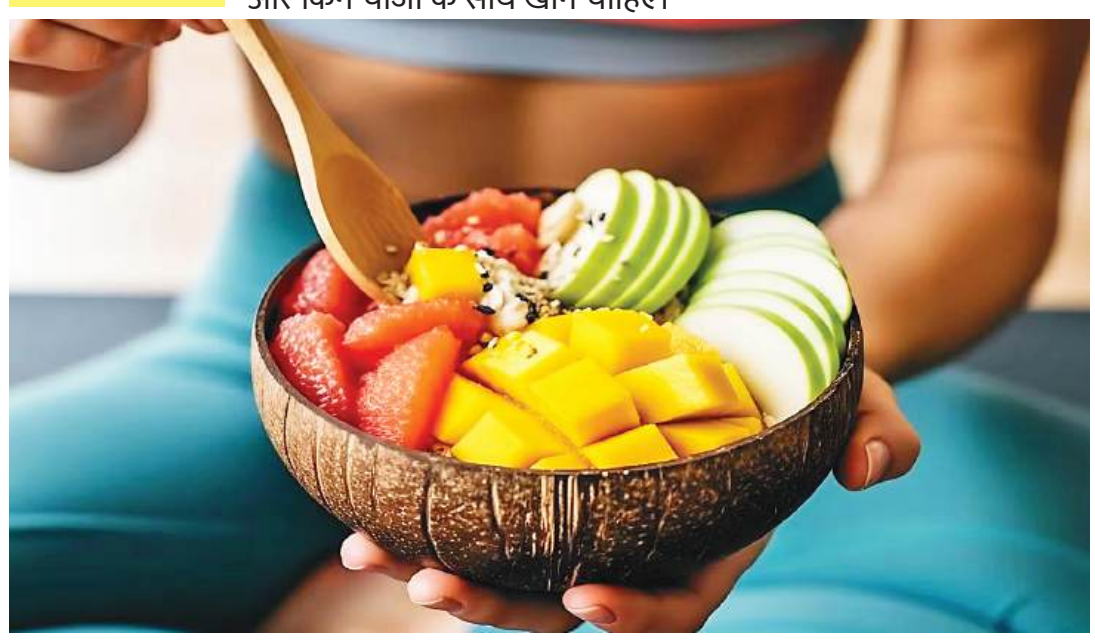

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

नाश्ते को दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है क्योंकि यही भोजन शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। ऐसे में बहुत से लोग सुबह के समय फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसे लेकर अक्सर भ्रम बना रहता है। कोई कहता है कि सुबह फल खाने से वजन बढ़ता है तो कोई इसे ब्लड शुगर बढ़ाने वाला मानता है। इस भ्रम को दूर करते हुए जसलोक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर, मुंबई की कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सोनल चंदालिया ने फलों को सुबह खाने के सही तरीके के बारे में बताया है।

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, अगर फल सही मात्रा और सही तरीके से खाए जाएं, तो वे दिन की शुरुआत के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। खासकर वे लोग जो सुबह एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, उनके लिए फल तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। फल शरीर को नेचुरल शुगर, फाइबर और जरूरी विटामिन्स प्रदान करते हैं जिससे थकान कम होती है और दिन की शुरुआत फ्रेश महसूस होती है।

कौन-से फल हैं बेहतर विकल्प?

सोनल चंदालिया बताती हैं कि मौसमी फल सबसे अच्छे माने जाते हैं। संतरा और मौसमी जैसे सिट्रस फल विटामिन c से भरपूर होते हैं जो इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अनार जैसे फल एंटीऑक्सिडेंट्स का अच्छा स्रोत हैं। वहीं, तरबूज और खरबूजा शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, जबकि केला पोटैशियम से भरपूर होकर एनर्जी लेवल बनाए रखता है।

फल खाने का सही तरीका

न्यूट्रिशनिस्ट सलाह देती हैं कि फलों को अकेले खाने की बजाय थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम या अखरोट के साथ खाना बेहतर होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और पेट में एसिडिटी की समस्या भी नहीं होती। यह कॉम्बिनेशन सुबह इम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है।

वजन घटाने में कैसे मददगार हैं फल?

फलों में मौजूद नेचुरल शुगर यानी फ्रक्टोज को 'स्लो शुगर' माना जाता है जो धीरे-धीरे पचती है। इससे बार-बार मीठा खाने की क्रेविंग कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

हालांकि फल सेहतमंद होते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसानदेह हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, एक समय में एक सर्विंग फल पर्याप्त है। खासकर फैटी लिवर या शुगर की समस्या वाले लोगों को पोर्शन कंट्रोल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

डिस्क्लेमर : यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

प्रगति पोर्टल : भारत की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला एक गेम चेंजर

• **जालंधर ब्रीज** . *नई दिल्ली*

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना आज़ादी के बाद शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई के लिए उच्च क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस विशेष रेल कॉरिडोर तैयार करना है।

इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल तेज़, सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत वाली लॉजिस्टिक सेवाएं देकर माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी दोबारा बढ़ाना चाहती है। साथ ही, इस परियोजना से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा।

करीब ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत और 2843 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के दो मुख्य हिस्से हैं:

पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(ईडीएफसी) : यह 1337 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल से लेकर बिहार के सोननगर तक जाता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से होकर गुजरता है।

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) : यह 1506 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक फैला हुआ है। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का मार्ग 7 राज्यों और 56 जिलों से होकर गुजरता है। यह जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों और क्रीक इलाकों से भी होकर जाता है, जिससे इस परियोजना का निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाता है।

समय पर पूरा होने में आने वाली चुनौतियां

हालांकि इस परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन कई बाधाओं के कारण कई वर्षों तक काम की गति धीमी रही। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार थीं : लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, जिसमें अवैध कब्जे और बने हुए ढांचों को हटाना शामिल था।

आर.के जैन
(पूर्व एमडी, डीएफसीसीआईएल)

वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों, पेड़ों की कटाई और क्रीक (नाले) पार करने से जुड़े कानूनी अनुमतियां प्राप्त करना।

900 से अधिक लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण, जिनके लिए संयुक्त नक्शा स्वीकृति और रास्तों के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था।

हाई टेंशन बिजली लाइनों, गैस और तेल पाइपलाइनों को स्थानांतरित करना।

रक्षा विभाग, एनएचएआई, राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों, सिंचाई विभाग से नहर पार करने की अनुमति और मिट्टी उधार लेने की स्वीकृति।

कोविड के बाद ठेकेदारों पर पड़ा आर्थिक दबाव, जिससे नकदी की कमी हुई।

निर्माण के लिए बिना किसी बाधा वाली भूमि उपलब्ध न होने से कार्य समय-सारिणी पर गंभीर असर पड़ा और परियोजना पर संभावित दावों का खतरा भी बढ़ गया।

प्रगति पोर्टल-निर्णायक मोड़ : प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुरू किया गया प्रगति पोर्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से डीएफसी के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं को पूरे दस्तावेज़ों के साथ अपलोड किया। प्रगति पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही थी। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विभागों को यह साफ़ पता था कि कार्य की प्रगति पर सबसे ऊंचे स्तर पर, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी, निगरानी की जा रही है।

जो मुद्दे वर्षों तक लगातार प्रयासों के बावजूद अटके रहे थे, वे कुछ ही हफ्तों में, और कई मामलों में तो कुछ दिनों के भीतर ही, सुलझा लिए गए। जहाँ तुरंत समाधान संभव नहीं था, वहाँ विभागों ने निश्चित समय-सीमा तय की और उसका सख्ती से पालन किया गया।

शासन और जवाबदेही की नई संस्कृति

प्रगति पोर्टल एक अत्यंत प्रभावी मंच के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से : परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी संभव हुई।

समस्याओं को एक साथ कई स्तरों तक तुरंत पहुँचाया जा सका

एक ही मंच से मंत्रालयों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो पाया

डीएफसी परियोजना में भी इसी तरह की एक आंतरिक निगरानी व्यवस्था लागू की गई। बड़े ठेकों की साप्ताहिक समीक्षा, नियमित स्थल निरीक्षण और तय किए गए लक्ष्यों की लगातार निगरानी सामान्य प्रक्रिया बन गई।

चूंकि पोर्टल पर डाली गई सभी समय-सीमाएं दर्ज रहती थीं, इससे परियोजना टीम के भीतर अपने वादों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही की भावना भी मज़बूत हुई।

परियोजना क्रियान्वयन पर स्पष्ट प्रभाव

जटिल समस्याओं के तेज़ समाधान से निर्माण कार्य में उल्लेखनीय तेजी आई और बिना बाधा वाली भूमि समय पर उपलब्ध न होने से होने वाले संभावित दावों से संगठन को सुरक्षा मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रगति पोर्टल ने रोज़मर्रा की परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही को शामिल करके पूरे शासन तंत्र की कार्यसंस्कृति को ही बदल दिया।

प्रगति पोर्टल आज प्रभावी डिजिटल शासन का एक जीवंत उदाहरण है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी विशाल परियोजना, जो कई राज्यों, विभागों और नियामक क्षेत्रों से होकर गुजरती है, के लिए प्रगति केवल एक निगरानी उपकरण नहीं रहा, बल्कि बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ।

तेज़ फैसले सुनिश्चित करके, विभागों के बीच टकराव कम करके और हर स्तर पर जवाबदेही तय करके, प्रगति पोर्टल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को सफल और समय पर पूरा करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। साथ ही, इसने भारत की आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक नया मानक भी स्थापित किया है।

कार्ययोजना के हाशिये से निर्णय के केंद्र तक

प्रगति और मिजोरम की रेल अवसंरचना

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

जब मैं 2015 में बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना में शामिल हुआ, तो मुझे लगता था कि यह देश के ऐसे हिस्से में कदम रखने जैसा है, जिस पर शायद ही कभी राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया गया हो। यह सफ़र खुद ही अपनी कहानी कहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-154, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग-06 कहा जाता है, एकमात्र पहुंच मार्ग था, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और भरोसे के लायक नहीं था। भारी ट्रक अक्सर कई दिनों तक फंसे रहते थे और निकटवर्ती स्थानों की यात्रा हिचकोलों से भरी होती थी। आस-पास की पहाड़ियाँ छोटी, कमजोर और अस्थिर थीं, जिनका आकार तीव्र वर्षा और निरंतर ढलान गति के कारण बदलता रहता था। कागज पर, परियोजना ऐतिहासिक थी, राष्ट्रीय नेटवर्क से मिजोरम का पहला रेल-परिवहन संपर्क, जो पहाड़ों, तीव्र ढलान और गहरी घाटियों को काट कर तैयार किया जा रहा था।

हालाँकि, ज़मीनी स्तर पर प्रगति बहुत धीमी थी। सामग्री की अनुपलब्धता, श्रम की कमी, परिवहन में विलंब, स्थानीय बाधाएं और लगातार स्थगित निर्णयों के कारण कार्यस्थल पर काम न होना आम बात थी। एक सुरंग डिज़ाइन सलाहकार और भूविज्ञानी के रूप में, भूविज्ञान कार्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसकी गंभीरता समझी जा सकती थी। जो बात वास्तव में अधिक कठिन साबित हुई, वह थी - संस्थागत निष्क्रियता। परियोजना देश के सबसे दूर-दराज के क्षेत्र में स्थित थी। समीक्षा छिटपुट थी। निर्णय लेने का अधिकार मंत्रालयों, राज्य विभागों और एजेंसियों में बिखरा हुआ था। धीरे-धीरे, एक असहज सच्चाई स्पष्ट होने लगी : ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी वास्तव में यह उम्मीद नहीं करता था कि परियोजना निकट भविष्य में पूरी होगी। फिर, शांतिपूर्वक और बिना किसी घोषणा के, पूरी प्रणाली में अचानक तेजी आयी। परियोजना कार्यालयों में एक स्पष्ट तत्परता का भाव दिखने लगा। फोन बार-बार बजने लगे। वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थलों का दौरा करने लगे। लंबे समय से लंबित फाइलों को तुरंत सामने लाया गया, उनकी समीक्षा की गई और उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा गया। बैठकें तेजी से व नियमित रूप से निर्धारित की जाने लगीं, अक्सर उन एजेंसियों को भी शामिल किया गया, जो पहले अलग-थलग रहकर काम करती थीं।

वरुण अधिकारी
(मुख्य इंजीनियरिंग भूविज्ञानी)

एक निजी सलाहकार के रूप में, मैं प्रशासनिक विभाग का हिस्सा नहीं था और किसी ने भी गतिविधि में आयी इस अचानक तेजी के पीछे का कारण नहीं बताया। लेकिन बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लंबे अनुभव ने मुझे संकेत की पहचान करना सिखा दिया था। यह सामान्य दबाव नहीं था। यह शीर्ष स्तर पर निरीक्षण की तैयारी थी। जल्द ही कारण स्पष्ट हो गया: बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना की समीक्षा पीएम की अध्यक्षता वाले सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच के तहत निर्धारित की गई थी। परियोजना लंबे समय तक हाशिये पर रही, लेकिन प्रगति के अंतर्गत समीक्षा से प्राधिकार व जवाबदेही तय हुई और हर लंबित मुद्दे तथा एजेंसियों के बीच अड़चनों के सम्बन्ध में वास्तविक समय पर जांच की व्यवस्था की गयी। इस बैठक के बाद निर्णय मेल खाने लगे, और प्रगति दिखाई दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार शासन अक्सर परिणाम तय करता है।

मार्च 2016 की प्रगति समीक्षा बैठक ने परियोजना के आयाम में मूलभूत बदलाव किये। इस रूपरेखा के तहत, समस्याओं की अलग-अलग जाँच नहीं की जा सकती थी और न ही उन्हें अनिश्चितकाल के लिए टाला जा सकता था। एन-एच-06 की अत्यंत खराब हालत अब रेलवे के कार्य क्षेत्र के बाहर नहीं मानी जा रही थी। स्पष्ट समयसीमा और निरंतर निगरानी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मरम्मत और सुधार कार्य करने का निर्देश दिया गया। भूमि अधिग्रहण में देरी को अब केवल सामान्य प्रशासनिक बाधाओं के रूप में नहीं देखा जा रहा था; मिजोरम सरकार को समाधान तेज करने का निर्देश दिया गया और प्रगति पर निगरानी रखी गई। कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को औपचारिक रूप से क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम माना गया और उन पर कड़ी निगरानी रखी गयी। व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि निर्णयों का समन्वय ही वह बात थी, जो सबसे अधिक ध्यान खींचती थी। प्रगति के तहत, एजेंसियां अब अलग-थलग रहकर काम नहीं कर सकती थीं। जिम्मेदारियां निर्धारित की गईं, समन्वय को अनिवार्य किया गया और अनुवर्ती कार्यों में निरंतरता लाई गयी।

इसका असर तुरंत दिखा, कटकहल-बैराबी खंड को मार्च 2016 में चालू किया गया, जिससे माल ढुलाई संभव हुई और पहुंच, लॉजिस्टिक्स और योजना में सुधार हुआ। जैसे-जैसे महीने बीतते गए, यह स्पष्ट हो गया कि प्रगति संस्थागत व्यवहार को बदल रही थी।

मिथ्या चेतना का दर्शनशास्त्र

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत में 2026 के आरंभ में सार्वजनिक बहस नववर्ष के अनुशासन के साथ शुरू होनी चाहिए। हमें पड़ताल और तीखी आलोचनाओं का भी स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि बहस के साथ जवाबदेही शामिल हो। कुल 1.4 अरब की आबादी वाले गणराज्य को निराशावाद से नहीं सुधारा जा सकता। रोजगार, उत्पादकता, निर्यात और समावेशन सबसे अच्छे समय में भी आसान नहीं होते। प्रगति डिजाइन, क्रियान्वयन, सुधार और परिमापन के नीरस मेल से आती है। नया साल निराशावाद को संशयवाद से अलग करने का भी क्षण है।

फ्रेडरिक नीत्शे ने 'बेयांड गुड एंड ईवल' में लिखा है: 'दार्शनिक को सिर्फ आलोचक या दर्शक होने के बजाय मूल्यों का सर्जक होना चाहिए। उसे तत्वचिंतन जीवन के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके नजरिए से करना चाहिए।' लोकनीति में इसी तरह के दृष्टिकोण की दरकार है। आलोचनाओं का स्वागत है। मगर ये साक्ष्य तथा एक जटिल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र का शासन चलाने की ज्वलंत बाधाओं से आबद्ध होनी चाहिए। जब संशयवाद एक भंगिमा बन जाए तो यह सुधार संभव बनाने वाली संस्थाओं में विश्वास को खत्म करता है।

हरदीप सिंह पुरी
(लेखक भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं)

पिछले वर्षों में टिप्पणी की एक नई विधा सामने आई है। यह संदेह को सुसंस्करण के तौर पर पेश करती है। यह सुधार के कार्य को मजाक में तब्दील कर देती है। यह हर अपूर्ण परिवर्तन को स्थाई नाकामी के सबूत के तौर पर लेती है। यह एक चिरपरिचित सांत्वना पेश करती है: भारत कदाचित अपने ही नीति निर्माताओं से अभिशप्त है। इस दृष्टिकोण के अपने नतीजे हैं। यह आंकड़ों और बाजारों में विश्वास को घटाता है। यह उद्यमियों और निवेशकों में नियतिवाद को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह बाहरी ताकतों को वार्ताओं में भारत को दबाव में लाने के लिए तैयार कथानक भी प्रदान करता है। विशेषज्ञता को तथ्यों के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए। मजबूत पेशेवर और शैक्षिक पृष्ठभूमि का दंभ भरने वाले कुछ टिप्पणीकारों का इस तरह की भंगिमा का सहारा लेना चिंता की बात है। इनमें से कुछ ऐसे टिप्पणीकारों को मैं जानता हूं जिनकी पहचान और विश्वसनीयता भारत पर आधारित है। लेकिन वे संभवत: ध्यानाकर्षण या अब सरकार का हिस्सा नहीं होने के बावजूद प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए देश के खिलाफ अनाप-शनाप बोल कर अपना कॅरियर बनाने की कोशिश में लगे हैं।

उनका यह आरोप कि भारत के आंकड़े विशिष्ट तौर पर अविश्वसनीय हैं, हमारी विकास की दिशा के साथ मेल नहीं खाते। माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत टैक्स संग्रह में जो वृद्धि हुई और इसने अनुपालन की जिस संस्कृति को पैदा किया है वह एक दशक पहले नहीं थी। वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। यानी औसतन प्रति माह 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह किया गया। डिजिटल भुगतान ने वित्तीय प्रदर्शन का एक और निशान छोड़ा है। नवंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 20 अरब लेन-देन किए गए। ये वृहत और परखे जाने योग्य आंकड़े परिमापन, सत्यापन और तौरतरीकों में सुधार के लिए संभावना का विस्तार करते हैं।

कल्याण और समावेशन में परिमापित परिणाम इस नियतिवाद की और हवा निकाल देते हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच लगभग 24 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। अब बहुआयामी निर्धनता लगभग 30 प्रतिशत से घट कर तकरीबन 11 प्रतिशत रह गई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से डिलीवरी दुरुस्त हुई है। वर्ष 2025 में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ।

विकसित भारत युवा नेता संवाद : विकसित भारत के लिए युवा नेतृत्व का सशक्तिकरण

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत की विकास कथा उन लोगों द्वारा लिखी जाएगी, जो आज इसके विचारों को स्वरुप दे रहे हैं। पूरे देश में, युवा भारतीय इस बारे में गहराई से सोच रहे हैं कि भारत कैसे तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, कैसे बेहतर शासन कर सकता है और किस प्रकार 2047 तक विकसित देश बन सकता है। उनके विचार विश्वविद्यालय परिसरों और समुदायों, स्टार्ट-अप और खेल के मैदानों, कक्षाओं और गांव की बैठकों में उभरकर सामने आ रहे हैं।

वास्तविक सवाल अब यह नहीं रहा कि क्या युवाओं के पास योगदान देने के लिए कुछ है, बल्कि यह है कि क्या उनके विचारों को राष्ट्र की दिशा को प्रभावित करने के लिए एक सशक्त मंच दिया जा रहा है। विकसित भारत युवा नेता संवाद (वीबीवाईएलडी) को ऐसा ही मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा केवल नीतियों या संस्थाओं से नहीं, बल्कि इसके युवा नागरिकों की कल्पना, दृढ़ विश्वास और साहस से निर्धारित होगी। विशाल युवा शक्ति का यह भंडार केवल जनसांख्यिकीय लाभ नहीं है; यह भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिसंपत्ति है, जो नवाचार को गति देने, लोकतंत्र को मजबूत करने तथा देश को समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम है।

डॉ. मनसुख मांडविया
(केंद्रीय मंत्री)

भारत की युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को मजबूत उद्देश्य और संभावना से मार्गदर्शन मिलता है। आज का युवा केवल व्यक्तिगत उन्नति से प्रेरणा प्राप्त नहीं करता है; वह जिम्मेदारी उठाने और सार्थक प्रभाव डालने की इच्छा से भी प्रेरित होता है। वे ऐसे रास्तों की खोज करते हैं, जहां उनकी रचनात्मकता, समाधानों में बदल सके, उनकी ऊर्जा नेतृत्व में और उनकी महत्वाकांक्षा सेवा में परिवर्तित हो सके।

युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मुझे विभिन्न पृष्ठभूमियों में - जैसे विश्वविद्यालय परिसरों में, ग्रामीण जिलों में, खेल मैदानों में और युवा नेतृत्व वाली सामुदायिक पहलों में - युवा भारतीयों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। जो चीज़ हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह यह है कि युवा लोग देश के भविष्य के बारे में कितनी गंभीरता से सोचते हैं। मुझे वह मौका याद है जब मैं ग्रामीण युवा स्वयंसेवकों के एक समूह से मिला, जिन्होंने अपने गाँवों में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का आयोजन किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद, दृढ़ विश्वास के साथ, वे शिक्षा और कौशल विकास की कमियों का स्थानीय रूप से डिज़ाइन किए गए उपायों के माध्यम से समाधान कर रहे थे। उनके विचार व्यावहारिक थे, जमीनी वास्तविकताओं से जुड़े थे और जिम्मेदारी की स्पष्ट भावना से संचालित थे। इस तरह के अनुभव एक सरल सच्चाई की पुष्टि करते हैं: जब युवा लोगों पर भरोसा किया जाता है और उन्हें स्थान दिया जाता है, तो वे केवल भाग नहीं लेते, बल्कि नेतृत्व करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से आह्वान किया था कि ऐसे एक लाख युवाओं को सार्वजनिक जीवन में लाया जाना चाहिए, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। प्रधानमंत्री की इसी भावना से प्रेरित होकर जनवरी 2025 में 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की परिकल्पना पूरी तरह से नए प्रारूप में की गयी है।

पंचायत उन्नति सूचकांक : ग्रामीण परिवर्तन के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने को मजबूत करना

• *जालंधर ब्रीज* . *नई दिल्ली*

भारत के गांवों में एक शांत लेकिन असरदार बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र की एक पंचायत में "महिला-अनुकूल पंचायत" विषय में कम अंक आने पर सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, वहीं गुजरात के एक गांव में "स्वच्छ और हरित पंचायत" श्रेणी में कमजोर प्रदर्शन के बाद तेजी से स्वच्छता अभियान शुरू किए गए।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) अब यह तय करने लगा है कि जमीनी स्तर पर विकास की योजना कैसे बने और उसे कैसे लागू किया जाए। कई पंचायतों में पीएआई के जरिए सामने आई कमियां जैसे संस्थागत प्रसव की कम संख्या, खराब कचरा प्रबंधन या पानी की कमी के आधार पर सीधे लक्षित कदम उठाए गए हैं।

सुशील कुमार लोहानी
(अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय)

ये शुरुआती उदाहरण एक सरल लेकिन मजबूत सच्चाई दिखाते हैं-जब पंचायतें अपनी ताकत और कमज़ोरियों को साफ़-साफ़ देख पाती हैं, तो वे ज़्यादा तेज़ी से और सही तरीके से काम करती हैं। कई दशकों तक भारत में ग्रामीण विकास ज़्यादातर हाथ से बनी रिपोर्टों, व्यक्तिगत धारणाओं और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहा। आज पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) ग्रामीण प्रशासन के केंद्र में एक नया मॉडल लेकर आया है, जो पारदर्शी है, आंकड़ों पर आधारित है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है।

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) भारत का पहला देशव्यापी ढांचा है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रगति को वस्तुनिष्ठ संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, शासन, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा, पर्यावरणीय स्थिरता आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह मूल्यांकन 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से निकले स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के नौ विषयों के अंतर्गत किया जाता है।

तर्कसंगत रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही आवश्यक है, जहां पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं। इस संदर्भ में, पीएआई ग्रामीण क्षेत्रों में एलएसडीजी और अंततः एसडीजी की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए एक साक्ष्य-आधारित व्यवस्था प्रदान करता है।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) की गणना एक मजबूत और बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसमें नौ विषयों के अंतर्गत 435 अलग-अलग स्थानीय संकेतकों का उपयोग होता है। पंचायती राज मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से परामर्श कर संकेतकों का ढांचा तैयार करता है, जबकि वास्तविक आंकड़े ग्राम पंचायतों और संबंधित विभागों द्वारा एक साझा पोर्टल pai.gov.in पर ग्राम पंचायत स्तर पर दर्ज किए जाते हैं।

इन आंकड़ों का सत्यापन कई प्रशासनिक स्तरों पर किया जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा जांच भी शामिल है। प्रत्येक विषय का स्कोर इन संकेतकों के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर तय होता है और इन्हीं से कुल पीएआई स्कोर (0-100) बनता है। इसी कुल स्कोर के आधार पर पंचायतों को तुलना के लिए पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किए गए पहले सर्वेक्षण से कई रोचक तथ्य सामने आए। सत्यापित आंकड़े जमा करने वाली 2.16 लाख पंचायतों में से कोई भी पंचायत "अचीवर" (90 से अधिक अंक) की श्रेणी में नहीं आई। केवल 0.3% पंचायतें "फ्रंट रनर" (75-89.99 अंक) रहीं और 35.8% पंचायतें "परफॉर्मर" (60-74.99 अंक) की श्रेणी में थी। सबसे अधिक, यानी 61.2% पंचायतें "आकांक्षी" (40-59.99 अंक) श्रेणी में रहीं, जबकि 2.7% पंचायतें "शुरुआती" (40 से कम अंक) श्रेणी में पाई गईं।

एलपीयू के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से भारत को 2047 तक विकसित भारत की ओर ले जाने के सफर में नेतृत्व करने का किया आह्वान

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पंजाब के फागवारा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और युवाओं से राष्ट्र और मानवता की सेवा में पेशेवर उत्कृष्टता को नैतिक जिम्मेदारी के साथ जोड़ने का आह्वान किया। विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण पर बोलते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में , देश ने एक विकसित, आत्मनिर्भर, समावेशी और आत्मविश्वासी भारत के निर्माण का महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास से परे है और इसमें सामाजिक सद्भाव, नैतिक नेतृत्व, सांस्कृतिक आत्मविश्वास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास शामिल हैं - इसकी प्राप्ति काफी हद तक युवाओं की ऊर्जा, क्षमता और चरित्र पर निर्भर करती है।

भारत की एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने की आकांक्षा को स्पष्ट करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्देश्य छोटे देशों पर शर्तें थोपना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अन्य देश भारत पर शर्तें न थोप सके। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो बात पांच साल पहले प्रासंगिक थी, वह जल्द ही अप्रासंगिक हो सकती है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है, और निरंतर सफलता के लिए अनुकूलनशीलता और आजीवन सीखना आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वे अपनी सफलता या असफलता की तुलना दूसरों से न करें, इस बात पर जोर देते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक अनूठा सफर और गति होती है। अब्राहम लिंकन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयास, दृढ़ता और ईमानदारी व्यक्तियों को साधारण शुरुआत से महान जिम्मेदारियों के पदों तक ले जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि केवल अपने लिए जीना गलत नहीं है, लेकिन केवल अपने लिए जीने से जीवन का व्यापक उद्देश्य कम हो जाता है। छात्रों के लिए तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए, उपाध्यक्ष ने उनसे प्रभावी समय प्रबंधन का अभ्यास करने, दीर्घकालिक सफलता को कमजोर करने वाले शॉर्टकट से बचने और कभी हार न मानने का आग्रह किया, साथ ही स्वामी विवेकानंद के प्रेरक शब्दों को याद दिलाया - "उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको।"

उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की जय जवान छात्रवृत्ति की भी सराहना की, जो सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के बलिदान को सार्थक शैक्षिक सहायता प्रदान करके सम्मानित करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी पहल इस बात की पुष्टि करती हैं कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायक संस्थान हैं।

मान सरकार ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें शुरू करने का लिया फैसला

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा- पंजाब की बसों में पारदर्शिता, दक्षता और यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करेगी स्मार्ट टिकटिंग

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

आधुनिक और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में अपने निर्णायक कदम जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी बस सेवाओं में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद को मंजूरी देकर सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह पहल नागरिकों के लिए रोज़मर्रा की सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने हेतु तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की शुरुआत पंजाब में यात्रियों की बस सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में एक अहम सुधार है। इस व्यवस्था के तहत यात्री विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों के माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे, जिनमें क्यूआर कोड आधारित भुगतान, यूपीआई, कार्ड आधारित लेन-देन और ऑफलाइन मोड शामिल हैं। यह प्रणाली प्रतीक्षा समय को कम करने, नकदी पर निर्भरता घटाने तथा शहरी और ग्रामीण दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

नई टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार यात्रियों की सुविधा और यात्रा संबंधी योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। ये मशीनें जीपीएस-सक्षम होंगी, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग, नजदीकी बस स्टॉप की जानकारी और विभिन्न मार्गों पर उपलब्ध सेवाओं से संबंधित वास्तविक समय की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। सीटों की उपलब्धता की जानकारी और यात्रा को अधिक कुशल बनाने की सुविधा के साथ सरकारी बस सेवाओं की विश्वसनीयता में और वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवंत मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी प्रमुख कल्याणकारी प्राथमिकताएं नई प्रणाली के तहत पूरी तरह सुरक्षित रहें। सरकार की नीति के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहेगी। महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आवागमन में सुविधा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हैं। विद्यार्थियों को भी स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा, जिससे युवाओं के लिए यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बनेगी।

इस पहल के तहत प्रस्तुत स्मार्ट कार्ड इकोसिस्टम नागरिकों और पर्यटकों को पंजाब सरकार की बसों में सहज यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। स्मार्ट कार्डों को मोबाइल एप के जरिए डिजिटल रूप से रिचार्ज किया जा सकेगा, जो सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से जोड़ने और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें परिवहन विभाग के कार्य संचालन को और अधिक सुचारु बनाएंगी। टिकट बिक्री और बसों की आवाजाही की वास्तविक समय निगरानी से राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी, मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा और जवाबदेही में वृद्धि होगी। सटीक डिजिटल डेटा की उपलब्धता बेहतर योजना निर्माण, उपयुक्त निर्णय लेने और बसों की अधिक कुशल तैनाती में सहायक होगी, जिससे मौजूदा फ्लीट में और वाहनों को शामिल कर सेवाओं का विस्तार संभव हो सकेगा। परिवहन मंत्री ने कहा, "नागरिकों को यह तकनीक उपलब्ध कराकर भगवंत मान सरकार जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के अपने व्यापक दृष्टिकोण को और मजबूत कर रही है। स्मार्ट टिकटिंग बुनियादी ढांचे की ओर यह कदम सुरक्षित, कुशल और तकनीक-आधारित परिवहन उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही यह प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि पंजाब में सार्वजनिक परिवहन समावेशी हो और लोगों की भलाई व जरूरतों पर केंद्रित रहे।"

पंजाब राज्य अल्पसंख्यक कमिशन के चेयरमैन ने सुनी अल्पसंख्यक भाईचारे से जुड़े लोगों की समस्याएं

अधिकारियों को उचित समाधान के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के दिए निर्देश

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जतिंदर मसीह गौरव ने आज यहां जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में अल्पसंख्यक भाईचारे से जुड़े लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को इनके उचित समाधान के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई लागू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एस.एस.पी. श्री गौरव तूरा, कमिश्नर नगर निगम अनुपम क्लेयर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) नवनीत कौर बॉल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (व) वरिंदरपाल सिंह बाजवा, डी.एस.पी. कपूरथला डॉ. शीतल सिंह तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

ईसाई भाईचारे की कब्रिस्तान संबंधी समस्याओं को सुनते हुए आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को ईसाई समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार करने में आ रही कठिनाइयों का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो जिम्मेदारों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चेयरमैन ने कहा कि अल्पसंख्यक भाईचारे को हर स्तर पर समान अधिकार मिलने और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं का सम्मान करना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक भाईचारे की पुलिस, नगर निगम सहित अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से इनका उचित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अल्पसंख्यक भाईचारे की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा धर्म के नाम पर आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि यदि कोई शरारती तत्व धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक भाईचारे को तंग-परेशान करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

वज्र कोर द्वारा 10वां रक्षा सेवा पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

वज्र कोर ने 10वां रक्षा सेवा पूर्व सैनिक दिवस पूरी गंभीरता, गर्मजोशी और भाईचारे की गहरी भावना के साथ मनाया, और भारत के पूर्व सैनिकों की अदम्य भावना, निस्वार्थ सेवा और स्थायी विरासत को दिल से श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्र ने उन लोगों के प्रति अपनी स्थायी कृतज्ञता को फिर से दोहराया, जिन्होंने इसकी संप्रभुता, एकता और मूल मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाने वाला रक्षा सेवा पूर्व सैनिक दिवस, भारत के पहले सेना कमांडर-इन-चीफ, फील्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करिअप्पा की सेवानिवृत्ति का प्रतीक है, और सशस्त्र बलों और उनके पूर्व सैनिकों के विस्तारित परिवार के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है।

इस अवसर पर, वज्र सैनिक संस्थान में दिल को छू लेने वाली बातचीत का आयोजन किया गया, जिसमें 280 से अधिक पूर्व सैनिक, वीर नारियां और परिवार के सदस्य एक साथ आए। मेजर जनरल अतुल भदौरिया, चीफ ऑफ स्टाफ, वज्र कोर ने सभा का गर्मजोशी से स्वागत किया और राष्ट्र की सेवा में उनके साहस, लचीलेपन और अतुलनीय बलिदानों के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राहत के दौरान उनके अटूट समर्थन को स्वीकार किया, और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, गरिमा और कल्याण के प्रति भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने पौने चार करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का नींव पत्थर रखा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/ खुरालगढ़ साहिब/होशियारपुर

श्री गुरु रविदास साहिब से संबंधित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल श्री खुरालगढ़ साहिब में मीनार-ए-बेगमपुरा से तप स्थान को जोड़ने वाले नए पुल का नींव पत्थर पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर स. जय कृष्ण सिंह रौड़ी द्वारा रखा गया। इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने बताया कि यह पुल पंजाब सरकार द्वारा लगभग पौने चार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, जो सदियों तक टिकाऊ रहेगा और संगतों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य को तय समय-सीमा के भीतर पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से पूरा करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का 650वां प्रकाश पर्व तप स्थान खुरालगढ़ साहिब में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस बड़े पर्व के मद्देनज़र सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करवाना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि संगतों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर गुरु घर के मुख्य सेवादार बाबा केवल सिंह द्वारा डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी और मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया गया। इसके साथ ही बाबा सुखदेव सिंह और बाबा नरेश सिंह द्वारा डिप्टी स्पीकर को सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस नींव पत्थर समारोह के दौरान विभिन्न गांवों के पंच-सरपंचों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

मोहाली वन मंडल की पहल से सिसवां-मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र बना ईको-टूरिज़्म का केंद्र : कटारूचक

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मोहाली वन मंडल द्वारा सिसवां-मिर्ज़ापुर वन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और ईको-टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए की जा रही पहलों को लोगों की ओर से अत्यंत उत्साहजनक सहयोग मिल रहा है। यह जानकारी देते हुए वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि सिसवां से मिर्ज़ापुर तक फैला नेचर ट्रैक, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है और जिसे पूरा करने में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे वन दृश्य, सुंदर व्यू पॉइंट्स और वॉच टावरों के कारण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है।

सिसवां डैम पर नौकायन (बोटिंग) की सुविधा, सुव्यवस्थित कैंटीन सेवाएं तथा तीन ईको-हट पर्यटकों को एक शानदार अनुभव प्रदान कर रही हैं। ये सभी सुविधाएं लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं।

इसके अलावा, वन मंडल द्वारा अन्य नेचर ट्रेल और ट्रैकिंग रूट भी विकसित किए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र ही आम जनता के लिए खोला जाएगा।

25 दिसंबर को सिसवां डैम पर एक सफल नेचर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पहले साइक्लिंग इवेंट और उसके बाद ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेष रूप से चंडीगढ़ के निवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

वाराणसी में प्रो. टीपी श्रीवास्तव ओरेशन से सम्मानित हुए पद्मश्री प्रो. डॉ. बीकेएस संजय

• **जालंधर ब्रीज.** देहरादून

वाराणसी ऑर्थोपीडिक एसोसिएशन ने ऑर्थोपीडिक्स, चिकित्सा शिक्षा, जनस्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री प्रो. डॉ. बी. के. एस. संजय, अध्यक्ष, एम्स गुवाहाटी को प्रतिष्ठित प्रो. टी. पी. श्रीवास्तव ओरेशन से सम्मानित किया। वाराणसी में आयोजित समारोह के दौरान प्रो. डॉ. संजय ने कहा कि चिकित्सकों की भूमिका केवल ऑपरेशन थिएटर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रोग-निवारण, जन-जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन में चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी पर ज़ोर देते हुए कहा कि डॉक्टर समाज के शिक्षक, संवादक और राष्ट्र-निर्माण के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। अपने व्याख्यान में प्रो. डॉ. संजय ने प्रभावी पेशेवर और सामाजिक सहभागिता के लिए अपने "7D दृष्टिकोण" को विस्तार से समझाया।

उन्होंने बताया कि सार्थक कार्य की शुरुआत प्रलेखन से होती है, इसके बाद प्रदर्शन और डेमॉन्स्ट्रेशन द्वारा विश्वसनीयता स्थापित की जाती है। इसके पश्चात ज्ञान का प्रसार और समाज व हितधारकों के साथ संवाद आवश्यक है, जिससे बेहतर निर्णय-निर्धारण संभव हो पाता है और अंततः प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज ही विकसित भारत की आधारशिला है और 7डी दृष्टिकोण केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी पेशों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

एनएचआरसी ने बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पिता से अलग हुए लड़के से बंधुआ मजदूरी कराए जाने की पीड़ा पर स्वतः संज्ञान लिया

• **जालंधर ब्रीज.** अंबाला

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- एनएचआरसी ने बिहार के किशनगंज जिले के एक 15 वर्षीय लड़के के हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने पिता से अलग होने के बाद महीनों तक बंधुआ मजदूरी कराए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी लेने ट्रेन से उतरा लेकिन भीड़ के कारण नहीं चढ़ सका। ट्रेन छूटने के बाद आठ महीने तक उसे बंधुआ मजदूरी की पीड़ा सहनी पड़ी। आखिरकार, कटी हुई कोहनी के साथ वह किसी तरह अपने घर वापस पहुंचा। समाचार रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि उसे अधिकारियों द्वारा अभी तक केंद्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना-2021 के तहत बंधुआ मजदूरी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जो पीड़ित के लिए पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट

के तथ्य सत्य हैं, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। मानवाधिकार आयोग ने इस सिलसिले में हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और बिहार के किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया कि पीड़ित को कोई मुआवजा और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के लाभ के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं। 12 जनवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद लड़का दो दिन तक रेलवे स्टेशन पर रुका रहा। इसके बाद एक व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ले जाकर सुबह से शाम तक मवेशी चराने और चारा काटने का काम करवाता रहा। उसे लगातार शारीरिक यातनाएं दी गईं। पीड़ित ने इस गुलामी से निकल भागने की असफल कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी दौरान चारा काटने की मशीन में पीड़ित का बायां हाथ फंसने से कोहनी से कट गया। मालिक ने उसका इलाज कराए बिना सड़क पर छोड़ दिया।

इसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति उसे हरियाणा के नूह जिले के एक अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां से पुराने मालिक के हाथों दोबारा पकड़े जाने के डर से वह भाग खड़ा हुआ और तीन किलोमीटर से अधिक नंगे पैर चलता रहा। तभी दो सरकारी शिक्षकों की उस पर निगाह पड़ी और मामले की सूचना हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित राजकीय रेलवे पुलिस -जीआरपी को दी गई। अंततः वह लड़का अगस्त 2025 में अपने घर लौट सका ।

जिला एवं सत्र न्यायधीश की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारटीज के सदस्यों के साथ बैठक

लोगों को 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी रजिंदर अग्रवाल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने नालसा से संबंधित स्कीमों को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। जिला व सत्र न्यायधीश ने जिला प्रशासन को कंपनसेशन टू विक्टम योजना के बारे में जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए ताकि सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सकें। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के साथ जुड़े एन.जी.ओज को हिदायत करते हुए कहा कि वे शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को नशा रोकथाम व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रति भी जागरुक करें। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता होती है। इस मौके पर सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी नीरज गोयल ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से अक्तूबर 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान 414 लोगों को लीगल एड, 132 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई। इसके अलावा अथारिटी की ओर से 876 सेमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 42 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 12 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए।

आईसीसी वनडे रैंकिंग में कोहली फिर नंबर-वन

फोटो- बीसीसीआई

स्पोर्ट्स डेस्क. वनडे क्रिकेट में विराट कोहली की शानदार फॉर्म ने उन्हें जुलाई 2021 के बाद पहली बार आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। कोहली ने रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत की जीत की नींव रखते हुए 91 गेंदों पर 93 रनों की तूफानी पारी खेली और अपने साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पुन: कब्जा जमा लिया। जुलाई 2021 के बाद यह पहली बार है जब दिग्गज क्रिकेटर ने वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। कोहली पहली बार अक्टूबर 2013 में शीर्ष पर पहुंचे थे और आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार अब यह उनका 11वां कार्यकाल है। अब तक उन्होंने शीर्ष पर कुल 825 दिन बिताए हैं - जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा कुल मिलाकर 10वां सबसे अधिक और किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। विराट कोहली पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत वनडे श्रृंखला के आखिरी मैच के बाद से शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने कल के मैच को छोड़कर पिछले सभी सात 50 ओवर के मैचों में पचास से अधिक का स्कोर बनाया है। उनकी पिछली सात पारियों के स्कोर इस प्रकार हैं: 93, 77 (विजय हजारे ट्रॉफी), 131 (विजय हजारे ट्रॉफी), 65, 102, 135 और 74।

2025 में कोहली ने 13 वनडे मैचों में 65.10 के शानदार औसत से 651 रन बनाए और कैलेंडर वर्ष में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे। अपने शानदार करियर में कोहली ने 11वीं बार आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रारूप में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। पिछले साल अक्टूबर में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद, कोहली ने सिडनी में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को वनडे सीरीज में सांत्वनापूर्ण जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। घरेलू मैदान पर वापसी करते हुए, उन्होंने नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 135, 102 और नाबाद 65 रन बनाए।

ब्राहमण भलाई बोर्ड के चेयरमैन पंकज शारदा ने मोहाली स्थित कार्यालय में संभाला पदभार

• **जालंधर ब्रीज.** लुधियाना

पंजाब सरकार द्वारा गठित ब्राहमण कल्याण बोर्ड के चेयरमैन पंकज शारदा ने आज मोहाली के वन भवन स्थित अपने कार्यलय में साथियों सहित पूजा अर्चना कर अपने कार्यालय की शुरुआत की इस अवसर पर शारदा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य प्रभारी मुनीश सिसोदिया का धन्यवाद करते हुये कहाकि वह सरकार द्वारा दी गई जुमेवारी का पूरी तनदेही से निर्वह करेंगे शारदा ने बताया कि वह हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अपने कार्यलय में उपस्थित रहेंगे यहां पर ब्राहमण समाज के सदस्य अपनी मुश्किलों के लिये उनसे मिल पाएंगे यहाँ यह भी बता दें कि शारदा द्वारा परशुराम सेवक संघ और पीपल

फार ऑर्फ़न आर्गेनाईजेशन के झंडे तले पिछले 15 सालों से लुधियाना में भगवान श्री परशुराम राम जी की भव्य यात्रा निकालने के साथ करीब 12000 हजार के करीब लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके है। इस अवसर पर राजीव शर्मा,दीपक मनन, राजू शर्मा, एडवोकेट रजनीश गुप्ता, रवी शर्मा, प्रभु शारदा अशवनी शारदा,विजय कपूर, कर्ण चांदला, धरमिंदर धामी, पंडित विजय शर्मा उपस्थित थे।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, J7 NEAR BUS STAND SUBHANPUR (HAMIRA), KAPURTHALA, PUNJAB - 144808, and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.